महाराष्ट्र स्वास्थ्य विश्वविद्यालय एस.सी. एवं अन्य

बनाम

सत्चिकित्सा प्रसारक मंडल और अन्य

(सिविल अपील क्रमांक 2050 ऑफ़ 2010)

25 फ़रवरी 2010

[जी.एस. सिंघवी और अशोक कुमार गांगुली, जे.जे.)

महाराष्ट्र विश्वविद्यालय स्वास्थ्य विज्ञान अधिनियम, 1998 - एस.एस. 2 (35) एवं 53-अप्रमाणित व्याख्याताओं द्वारा शिकायत कॉलेज और उसके प्राधिकारी - शिकायत समिति के अंतर्गत गठित। 53 प्राधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करना - उच्च कोर्ट ने एजुस्डेम जेनेरिस के सिद्धांत का पालन करते हुए ऐसा माना चूंकि अस्वीकृत शिक्षक परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं 'शिक्षकों' यूएलएस का 2(35), समिति को कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है शिकायत का संज्ञान लें- आयोजित: शिक्षकाओं की परिभाषा धारा 2(35) इतना विस्तृत है कि इसमें गैर-अनुमोदित शिक्षक भी शामिल हो सकते हैं- शिकायत समिति को सुनवाई का अधिकार है शिकायत करें और उल द्वारा प्रदत्त वैधानिक कार्यवाही करें। अधिनियम की धारा 53-मामला उच्च न्यायालय को प्रेषित।

क़ानून की व्याख्या - जब सामान्य शब्द हों विशिष्ट शब्दों के साथ तुलना करने पर सामान्य शब्द नहीं पढ़े जा सकते अलगाव में - उनके रंग और सामग्री से प्राप्त किया जाना है उनका सन्दर्भ-एजुस्डेम जेनेरिस सिद्धांत ही लागू होता है जब कोई विपरीत इरादा प्रकट न हो - कोई भी क़ानून ऐसा नहीं कर सकता इस तरह से व्याख्या की जाए कि इसका एक हिस्सा निरर्थक हो जाए- सिद्धांत/सिद्धांत - "ईज्यूसडेम जेनेरिस" का सिद्धांत की प्रयोज्यता - पर चर्चा की गई।

प्रतिवादी संख्या 5 और 6 (प्रतिवादी-कॉलेज की महिला व्याख्याता और कर्मचारी) की ओर से उक्त कॉलेज के अधिकारियों के खिलाफ दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न की शिकायत पर, विश्वविद्यालय की शिकायत समिति ने अपने संचार द्वारा पहले और दूसरे उत्तरदाताओं को तीसरे और चौथे उत्तरदाताओं को निलंबित करने के निर्देश के साथ उनके खिलाफ कदम उठाने होंगे और इस को यह भी निर्देश दिया गया कि पांचवें प्रतिवादी को बहाल किया जा सकता है। यह भी निर्देश दिया गया कि तीसरे और चौथे प्रतिवादी की सेवा के संबंध में दी गई मंजूरी को रोक दिया जाए। प्रतिवादी-कॉलेज ने विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देश का पालन करने से इनकार कर दिया।

उन संचारों पर हमला करते हुए, कॉलेज अधिकारियों और उन दो शिक्षकों ने एक रिट याचिका' दायर की यह तर्क देते हुए कि विश्वविद्यालय

के पास एन? एक अथॉरिटी मुद्दा वे संचार. उच्च न्यायालय, निम्नलिखित "ईजुस्डेम जेनेरिज" का सिद्धांत 5 वें और 6 वें को मानता है प्रतिवादी, अस्वीकृत शिक्षक होने के कारण नहीं आते हैं 'शिक्षकों' की परिभाषा के अंतर्गत। 2(35) और इसलिए, शिकायत समिति का गठन किया गया। 'अधिनियम के 53, है उनकी शिकायत पर संज्ञान लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसलिए वर्तमान अपील पेश की।

न्यायालय ने अपील की अनुमति देते हुए अभिनिर्धारित किया:-

1. अनुभाग के संयुक्त पाठन को ध्यान में रखते हुए 2(35) महाराष्ट्र विश्वविद्यालय स्वास्थ्य की धारा 53 के साथ गैर अनुमोदित शिक्षकों के संबंध में विज्ञान अधिनियम, 1998 नहीं कहा जा सकता कि ग्रीवेंस कमेटी के पास नहीं है शिकायत पर विचार करने और कार्रवाई करने का अधिकार क्षेत्र की धारा 53 के तहत इसे वैधानिक अभ्यास प्रदान किया गया कार्यवाही करना। [पैरा 20] [102-बी]

2. धारा के अंतर्गत शिक्षकों की परिभाषा। 2 (35) काफी चौड़ा है' में गैर-अनुमोदित शिक्षक को भी शामिल किया जाएगा। परिभाषा है दो भाग, पहला भाग पूर्णकालिक अनुमोदन से संबंधित है प्रदर्शनकारी, शिक्षक; सहायक व्याख्याता, व्याख्याता आदि और दूसरा भाग अन्य व्यक्तियों से संबंधित है में पूर्णकालिक आधार पर पढ़ाना या निर्देश देना में संबद्ध कॉलेज या अनुमोदित संस्थान विश्वविद्यालय। [पैरा 21] [102-सी-डी]

3. भले ही अनुमोदित शिक्षक और वे 'अन्य व्यक्ति' जो पढ़ा रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं दो अलग-अलग वर्गों में आता है, दोनों ही इसमें शामिल हैं, शिक्षक की परिभाषा अधिनियम की धारा 2(35)। शब्द ए 'अन्य व्यक्तियों' से पहले 'और' विभक्तिवाचक है और एक को इंगित करता है लोगों का अलग वर्ग। [पैरा 22] [102-ई]

4. एक वर्ग अपने अंदर समाहित करने वाली एक वैचारिक रचना है समान व्यक्तियों की अनेक श्रेणियाँ जोड़ें विशेषताएँ। यहाँ 'अन्य व्यक्तियों' के समूह में जो, 8 पूर्णकालिक आधार पर पढ़ा रहे हैं या निर्देश दे रहे हैं कॉलेज विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं और वे भी हैं शिक्षक भले ही वे अस्वीकृत हों। ऐसा लगता है अधिनियम की धारा 2(35) का तात्पर्य। [पैरा 23] (102-एफ-जी)

5. हाई कोर्ट ने उचित सराहना नहीं की दायरे को समझने में एजुस्डेम जेनेरिस का सिद्धांत अधिनियम की धारा 2 (35) आरएफडब्ल्यू धारा 53 की। इजहार "इजुस्डेम जेनेरिस" जिसका अर्थ है "एक ही प्रकार का या प्रकृति का" निर्माण का एक सिद्धांत है, जिसका अर्थ है जब किसी वैधानिक पाठ में सामान्य शब्द एक दूसरे से घिरे हों प्रतिबंधित शब्द, सामान्य शब्दों के अर्थ हैं के अर्थ के साथ निहितार्थ द्वारा प्रतिबंधित माना जाता है प्रतिबंधित शब्द, यह एक सिद्धांत है जो "ई" से उत्पन्न होता है भाषाई निहितार्थ जिससे शब्दों का शाब्दिक अर्थ होता है एक व्यापक अर्थ (जब

अलग से लिया जाता है) के रूप में माना जाता है मौखिक संदर्भ से इसका दायरा कम हो गया है।" यह हो सकता है इलिप्सिस या निर्भरता का एक उदाहरण माना जाता है निहितार्थ. यह सिद्धांत तब तक लागू माना जाता है जब तक कुछ विपरीत संकेत है. [पैरा 25 और 26] [103-ए; 103-बी-डी]

'एजुस्डेम की उत्पत्ति और तार्किक निहितार्थ जेनरिस रूल' ग्लेनविल विलियम्स द्वारा, 7 रूपांतरण (एनएस) 119, करने के लिए भेजा।

6. एजुस्डेम जेनेरिस सिद्धांत 1 का एक पहलू है। 'नोस्किटुर ए सोसिस' का सिद्धांत, जो इस बात पर विचार करता है कि ए वैधानिक शब्द की पहचान उससे जुड़े शब्दों से होती है। जब सामान्य शब्दों की तुलना विशिष्ट शब्दों से की जाती है, सामान्य शब्दों को अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता। इनका रंग ए और उनकी सामग्री उनके संदर्भ से प्राप्त की जानी है। [पैरा 27] (103-ई-एफ)

अटॉर्नी जनरल बनाम हनोवर के प्रिंस अर्नेस्ट ऑगस्टस, (1957) एसी 436 एट 461, संदर्भित।

7. एजुस्डेम जेनेरिस सिद्धांत केवल तभी लागू होता है जब विपरीत मंशा प्रकट नहीं होती। उस तत्काल मामले में, एक विपरीत इरादे को स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है अधिनियम की धारा 2(35) के तहत 'शिक्षकों' की परिभाषा है दो भागों में. पहला भाग। गणना से संबंधित है श्रेणियाँ लेकिन दूसरा भाग जो से शुरू होता है अभिव्यक्ति "और अन्य" की एक

अलग श्रेणी की परिकल्पना करती है व्यक्ति. यहाँ 'और' विभक्तिवाचक है। तो, व्याख्या करते समय ऐसी परिभाषा, एजुस्डेम जेनेरिस का सिद्धांत नहीं हो सकता लागू हो जाए। [पैरा 28] [103-जी-एच; 104-ए]

डी के.के. कोचुनी बनाम मद्रास और केरा राज्य/एआईआर 1960 एससी 1080, पर भरोसा किया।

क़ाज़ी बनाम क़ाज़ी (1979) 3 ऑल इंग्लैंड रिपोर्ट्स 897 संदर्भित किया,

8. किसी भी क़ानून की व्याख्या इस प्रकार नहीं की जा सकती जैसे·इसके एक भाग को ओटिवोज़ प्रस्तुत करें। जहां एक अलग बात है विधायी आशय, जैसा कि वर्तमान मामले में है, का सिद्धांत एजुस्डेम जेनेरिस को एक हिस्सा बनाने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है परिभाषा पूरी तरह से बेमानी. [पैरा 33 और 34] [105-एफ; 105-जी]

अमर चंद्र चक्रवर्ती बनाम उत्पाद शुल्क कलेक्टर, सरकार त्रिपुरा, अगरतला और अन्य के। एआईआर 1972 एससी 1863 पर संदर्भित।

9. इतना संकीर्ण और काट-छाँट करके धारा के अंतर्गत 'शिक्षकों' की व्याख्या। 2(35), उच्च न्यायालय ने नहीं किया है केवल धारा 2(35) के एक भाग को नजरअंदाज किया गया है लेकिन यह भी दिया गया हैएक व्याख्या जो स्वीकृत के साथ असंगत है अधिनियम की धारा 53 का उद्देश्य [पैरा 35] (105-एच; 106-ए)

10. उच्च न्यायालय ने यह कहकर गलती कर दी कि शिकायत समिति के पास 5 वें और 6 वें प्रतिवादी द्वारा की गई शिकायतों पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि वे अनुमोदित शिक्षक नहीं हैं। शिकायत समिति की स्थापना का उद्देश्य अधिनियम का धारा 53 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को एक प्रभावी शिकायत निवारण मंच प्रदान करना है। अधिनियम की धारा 2 (35) के तहत 'शिक्षकों' की कोई भी व्याख्या, जो धारा 2 (35) के तहत आने वाले व्यक्तियों को उक्त मंच तक पहुंच से वंचित करती है, ऐसे मंच बनाने के प्रमुख उद्देश्य को पूरी तरह से समाप्त कर देती है। इस मंच के संरक्षण की आवश्यकता अनुमोदित शिक्षकों से अधिक गैर अनुमोदित शिक्षकों को है। इस तरह का एक मंच बनाकर, विश्वविद्यालय ने वस्तुतः अनुमोदित और गैर-अनुमोदित दोनों शिक्षकों और जो इससे संबद्ध विभिन्न कॉलेजों में काम कर रहे हैं, पर लोको-पेरेंटिस के रूप में अपने अधिकार और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है। विचार यह है कि ऐसे शिक्षकों और कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से सुरक्षा दी जाए। ऐसे मंच का निर्माण 'व्यक्ति की गरिमा' की रक्षा के अनुरूप है जो मूल संवैधानिक अवधारणाओं में से एक है। इसलिए, इस प्रमुख वैधानिक उद्देश्य को विफल करने के लिए एजुस्डेम जेनेरिस के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है। [पैरा 36, 37 और 38] [106-बी-डी; 106-ई]

गाए टी. हेल्वरिंग बनाम स्टॉकहोम एनस्किल्डा बैंक 293 यूएस 84, 88-89, 79 एलईडी 211, 55 एस सीटी 50, 52 (1934), संदर्भित।

11. मामला उच्च न्यायालय को प्रेषित किया जाता है टिप्पणियों के आलोक में रिट याचिका का निपटारा करें इस निर्णय में शिकायत के क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है समिति। हालाँकि, बहाली का आदेश बना 5 वें और 6 वें प्रतिवादी का सम्मान बरकरार रखा जाएगा और सेवा में उनकी निरंतरता को भंग नहीं किया जा सकता है विश्वविद्यालय अधिनियमों के प्रावधानों का पालन किए बिना और क़ानून. [पैरा 41] [107-ई-एफ]

केस कानून संदर्भ:

1979 (3) ऑल-इंग्लैंड रिपोर्ट 897	संदर्भित को।	पैरा 29
एआईआर 1960 एससी 1080	पर भरोसा किया।	पैरा 30
एआईआर 1972 एससी 1863	पर भरोसा किया।	पैरा 31

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2050/2010।

उच्च न्यायिक न्यायालय बॉम्बे, नागपुर बेंच सन् 2006 की याचिका संख्या 1976 के रिट में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 08.06.2007 से।

यू.यू. ललित, प्रसेनजीत केसवानी और गौरव अग्रवाल अपीलकर्ता के लिए।

सत्यजीत ए.देसाई, अनघा एस.देसाई और जी.रामकृष्ण प्रसाद उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय द्वारा निर्णय अभिनिर्धारित किया गया

गांगुली, जे. 1. स्वीकृती अनुमोदित।

2. महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने अपने रजिस्ट्रार और इसकी शिकायत समिति और प्रबंधन परिषद के माध्यम से अपीलकर्ता के रूप में प्रबंधन परिषद और कर्मचारियों द्वारा दायर कई रिट याचिकाओं पर बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ द्वारा दिए गए दिनांक 8.6.07 के फैसले को चुनौती दी।

3. मामले के मूल तथ्य इस प्रकार हैं:

अपीलकर्ता नंबर 1, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का गठन महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज अधिनियम, 1998 (संक्षेप में 'उक्त अधिनियम') के तहत किया गया है। दूसरा अपीलकर्ता उक्त अधिनियम की धारा 53 के तहत गठित समिति है और तीसरा अपीलकर्ता अपीलकर्ता नंबर 1 की प्रबंधन परिषद है और उक्त अधिनियम के तहत भी गठित है।

4. इस अपील में पहला प्रतिवादी एक सार्वजनिक ट्रस्ट है बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 और के तहत पंजीकृत उक्त ट्रस्ट दूसरे

प्रतिवादी सहित कई कॉलेज चलाता है। तीसरा प्रतिवादी उक्त कॉलेज का प्राचार्य है और चौथा प्रतिवादी वहां एक व्याख्याता है। 5 वीं और 6 वीं दोनों उत्तरदाताओं को उक्त कॉलेज में व्याख्याता नियुक्त किया गया था लेकिन उनकी नियुक्तियों को मंजूरी नहीं दी गई लेकिन वे जारी रहीं उक्त महाविद्यालय में व्याख्याता के रूप में कार्य करें।

5. 7.8.05 को 5 तारीख को अभ्यावेदन दिया गया प्रतिवादी को इस आशय का जवाब देना होगा कि उसके द्वारा उक्त सी की सेवा करने के बाद पिछले साढ़े तीन साल से अचानक वह कॉलेज चली गई 6.8.05 को सूचित किया गया कि कॉलेज अधिकारियों ने उसका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। 5 वीं प्रतिवादी के बाद से यह उसके लिए चौंकाने वाला था वह कभी इस्तीफा नहीं दे सकती थीं क्योंकि उन पर कई देनदारियां थीं और कुछ भी नहीं अन्य कमाई। उसके दो बच्चों की पढ़ाई-लिखाई होनी थी जब उनके पति के कारण विकलांग थे तब उनकी देखभाल की गई दुर्घटना और उसके ससुर एक सेवानिवृत्त व्यक्ति थे। उसके अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय के कुलपति को प्रतिनिधित्व उसने कहा कि उसकी नियुक्ति के समय, कॉलेज अधिकारियों ने बिना त्यागपत्र पर उसके हस्ताक्षर ले लिए किसी भी तारीख का उल्लेख करना और उसका उपयोग को हटाने के लिए किया गया हो सकता है उसे कॉलेज से उक्त प्राप्ति पर विश्वविद्यालय प्रतिनिधित्व ने 19 अगस्त को उक्त महाविद्यालय को पत्र भेजा। इसके स्पष्टीकरण हेतु 2005

एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। दिनांक 31.08.05 को महाविद्यालय ने कहा।

6. इसके बाद, अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय ने 5 वें प्रतिवादी की शिकायत पर गौर करने के लिए एक समिति का गठन किया और उक्त समिति ने कॉलेज का दौरा करने और 29.08.05, 01.09.05 और 02.09.05 को जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय को सौंपी।

7. पुनः दिनांक 09.09.05 को 5 वें प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया की शिकायत समिति को एक और अभ्यावेदन अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय जिसे उक्त को भी भेजा गया था महाविद्यालय से उसकी प्रतिक्रिया हेतु। जिसे उक्त कॉलेज द्वारा जमा किया गया था। 04.10.05 और 08.11.05 को इसके बाद, अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय ने पांचवें प्रतिवादी को उसकी शिकायत के संबंध में सुनवाई का मौका दिया जिसे उन्होंने अपने प्रतिवेदन में उठाया था। उक्त बैठक थी शिकायत समिति और परिवाद के समक्ष रखा गया कमेटी ने अपनी जांच के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट दी. रिपोर्ट दिए जाने से पहले, 5 वां प्रतिवादी और व्यक्ति जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, उसके साथ जांच की गई कुछ गवाह. वहाँ, शिकायत समिति ने एक निर्णय लिया मामले को राज्य आयोग को सौंपने का निर्णय आगे की जांच

के लिए महिलाओं और यह निर्णय लिया गया कि उक्त आयोग की रिपोर्ट पर अगले में विचार किया जाना था समिति की बैठक.

8. इसके बाद 18 जनवरी, 2006 को छठा प्रतिवादी के खिलाफ थाना सदर में एक और शिकायत दर्ज कराई चौथा प्रतिवादी किस अपराध के परिणामस्वरूप दंडनीय है चौथे प्रतिवादी के खिलाफ एल.पी.सी की धारा 509 दर्ज की गई थी और सारांश आपराधिक मामला। क्रमांक 4332/06 दर्ज किया गया जे.एम.एफ.सी., नागपुर के न्यायालय में। 19.01.06 को 5 वां प्रतिवादी के आधार पर थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई उक्त रिपोर्ट पर दिनांक 04.02.06 को अपराध पंजीबद्ध किया गया अपराध संख्या 22/06 धारा 468, 471, 354, 509, 506 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पढ़ें। कनेक्शन में उपरोक्त आपराधिक मामले के साथ, तीसरे और चौथे उत्तरदाता पुलिस द्वारा दिनांक 05.02.06 को गिरफ्तार किया गया तथा रिमांड पर लिया गया दो दिन की पुलिस हिरासत में. द्वारा उन्हें जमानत दे दी गई न्यायालय जे.एम.एफ.सी., नागपुर दिनांक 08.02.06. के प्राचार्य दिनांक 06.02.06 को एफ कॉलेज को अग्रिम जमानत भी दे दी गई जिसके आदेश की बाद में 23.02.06 को पुष्टि की गई।

9. फिर 18.02.06 को छठे प्रतिवादी की सेवाएं उक्त कॉलेज द्वारा समाप्त कर दिया गया।

10. छठे प्रतिवादी की शिकायत को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने पहले, दूसरे और चौथे उत्तरदाताओं को सुनवाई के लिए बुलाया शिकायत समिति के समक्ष 08.03.06 को और 04.03.06 को 'छठे प्रतिवादी ने अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय को शिकायत भेजी उत्तरदाताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग। उस शिकायत में 6 वें प्रतिवादी ने दुर्व्यवहार और यौन संबंध का विवरण दिया. उनका और अन्य महिला व्याख्याताओं और कर्मचारियों का उत्पीड़न 5 वें प्रतिवादी सहित कॉलेज के अधीन थे उक्त कॉलेज के अधिकारियों द्वारा। ऐसी शिकायतों को देखते हुए 8 मार्च को विश्वविद्यालय की शिकायत समिति की बैठक हुई। 2006 में प्राप्त शिकायतों के आलोक में मुद्दों पर विचार किया गया छठे प्रतिवादी द्वारा कॉलेज प्राधिकारियों के विरुद्ध। अनुसरणकर्ता शिकायत समिति की बैठक में विश्वविद्यालय द्वारा इसके संचार दिनांक 21 मार्च, 2006 ने 1 और निर्देशित किया दूसरे उत्तरदाताओं को तीसरे और चौथे के खिलाफ कदम उठाना होगा उत्तरदाताओं को निलंबित करने का निर्देश दिया गया और यह भी किया गया निर्देश दिया कि पांचवें प्रतिवादी को बहाल किया जा सकता है। यह भी सी था निर्देश दिया कि 3 की सेवा के संबंध में अनुमोदन प्रदान किया जाए और चौथे प्रतिवादी को फ्रीज कर दिया जाए। 1 द्वारा उत्तर भेजा गया अपीलार्थी-विश्वविद्यालय दिनांक के आदेश का प्रतिवादी 21.03.06 इसके बाद, अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय ने आगे सूचित किया कॉलेज अधिकारियों ने कहा

कि तीसरे और चौथे उत्तरदाताओं के अनुमोदन को रोकने का निर्णय प्रावधान के तहत लिया गया था विश्वविद्यालय निर्देश संख्या 25/01 के खंड 25.2 का और यह था। उक्त अधिनियम की धारा 16(8) के अनुसार किया गया। प्रतिवादी कॉलेज के शासी निकाय की बैठक हुई द्वारा 27.03.06 को जारी निर्देश का अनुपालन करने से इंकार कर दिया विश्वविद्यालय ने अपने पत्र दिनांक 21 मार्च 2006 द्वारा यह तथ्य उक्त कॉलेज द्वारा अपीलकर्ता को सूचित किया गया। 1 अप्रैल को 2006, प्रथम और द्वितीय उत्तरदाताओं ने एक पत्र को संबोधित किया उसी तारीख और उसमें तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय नियुक्ति के अनुमोदन पर रोक लगाने की शक्ति नहीं है तीसरे और चौथे उत्तरदाताओं और एफ जैसे स्थायी शिक्षकों की संख्या अपीलकर्ता को अपना दिनांकित 29 मार्च 2006 संचार वापस लेने के लिए कहा गया था।

11. 21 मार्च के उन संचारों पर हमला करना, 2006 और 29 मार्च, 2006 को अपीलकर्ताओं, प्रतिवादियों अर्थात्, ट्रस्ट, कॉलेज प्राधिकारी और वे दो शिक्षकों ने 1976/06 में एक रिट याचिका दायर की अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय के पास इन्हें जारी करने का कोई अधिकार नहीं है संचार उस रिट कार्यवाही की सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतियोगिता में की गई।

12. आक्षेपित निर्णय दिनांक 08.06.07 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और इसे रद्द कर दिया की गई कार्यवाही के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा पारित आदेश के आरोपों के आधार पर उन उत्तरदाताओं के खिलाफ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के 5 वें और 6 वें प्रतिवादी।

13. उक्त निर्णय को चुनौती देते हुए इस न्यायालय का रुख किया गया है।

14. मुख्य प्रश्न जिस पर मामले पर बहस हुई अपीलकर्ताओं का कहना था कि उच्च न्यायालय ने यह निर्णय लेने में गलती की कि उक्त अधिनियम की धारा 53 के तहत गठित शिकायत समिति को 5 वें और 6 वें प्रतिवादी द्वारा दायर किसी भी शिकायत का संज्ञान लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि वे अनुमोदित प्रतिवादी कॉलेज शिक्षक नहीं हैं।

15. इस तर्क में शामिल कानूनी मुद्दों की सराहना करने के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 2 (35) के तहत 'शिक्षक' की परिभाषा निर्धारित करना बेहतर है। उक्त अधिनियम की धारा 2 (35) निम्नानुसार चलती है:-

"2(35) "शिक्षक" का अर्थ है पूर्णकालिक अनुमोदित

प्रदर्शनकारी, शिक्षक, सहायक व्याख्याता, व्याख्याता, पाठक, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और अन्य व्यक्ति जो विश्वविद्यालय में संबद्ध कॉलेजों या अनुमोदित संस्थानों में पूर्णकालिक आधार पर पढ़ाते या निर्देश देते हैं:"

16. उक्त अधिनियम की धारा 53 निम्नानुसार प्रावधान करती है:

"53. (1) इसमें एक शिकायत समिति होगी शिक्षकों और अन्य की शिकायतों से निपटने के लिए विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों, संस्थानों आदि के कर्मचारी मान्यता प्राप्त संस्थान और शिकायतें सुनने और निपटाने के लिए जहां तक संभव हो छह महीने के भीतर, और समिति प्रबंधन को एक रिपोर्ट देगी परिषद।"

(2) यह शिकायत समिति के लिए वैध होगा शिकायतों या शिकायतों का मनोरंजन करना और उन पर विचार करना और ऐसी कार्रवाई करने के लिए प्रबंधन परिषद को रिपोर्ट करें जैसा उचित समझे और प्रबंधन का निर्णय ऐसी रिपोर्ट पर परिषद अंतिम होगी।

(3) शिकायत समिति: इसमें शामिल हैं निम्नलिखित सदस्य, अर्थात्:

(ए) प्रो-वाइस चांसलर, - अध्यक्ष

(बी) प्रबंधन परिषद के चार सदस्य प्रबंधन परिषद द्वारा इनमें से नामित स्वयं - सदस्य

(सी) रजिस्ट्रार - सदस्य सचिव

(4) रजिस्ट्रार को वोट देने का अधिकार नहीं होगा।"

17. उपरोक्त दो धाराओं का अर्थ लगाते हुए, उच्च न्यायालय, ओ "ईजुस्डेम जेनेरिस" के सिद्धांत का पालन करते हुए 5 वें और का आयोजन किया गया छठा प्रतिवादी, अस्वीकृत शिक्षक होने के कारण, भीतर नहीं आता है। ऊपर उद्धृत धारा 2(35) के तहत 'शिक्षकों' की परिभाषा।

18. यह न्यायालय नीचे बताए गए विभिन्न कारणों से उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय को स्वीकार नहीं कर सकता है।

19. यदि शिक्षकों की परिभाषा, जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, का ठीक से अध्ययन किया जाए तो यह प्रतीत होगा कि शिक्षकों की परिभाषा में न केवल पूर्णकालिक अनुमोदित प्रदर्शनकारी, ट्यूटर, सहायक व्याख्याता आदि शामिल हैं, बल्कि परिभाषा इतनी व्यापक है कि इसमें शामिल किया जा सकता है, और अन्य व्यक्ति विश्वविद्यालय में संबद्ध महाविद्यालयों या अनुमोदित संस्थानों में पूर्णकालिक आधार पर पढ़ा रहे हैं या निर्देश दे रहे हैं।" इसी प्रकार, उक्त अधिनियम की धारा 53 के तहत गठित शिकायत समिति को भी न केवल शिक्षकों बल्कि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, संस्थान के अन्य कर्मचारियों की शिकायतों से निपटने और

उनकी शिकायतों का निपटारा करने के लिए व्यापक अधिकार दिए गए हैं। एक निश्चित समय-सीमा के भीतर व्यवहार्य हो सकता है। उक्त अधिनियम की धारा 53 की उपधारा (2) परिणामी कदमों का प्रावधान करती है जो शिकायत समिति उठा सकती है। श्रेणी के व्यक्तियों की शिकायतों पर विचार करने के बाद धारा 53 (1) में नामित। धारा 53 (3) का प्रावधान है शिकायत समिति का गठन एवं धारा 53(4) प्रकृति में प्रक्रियात्मक है।

20. धारा 2 (35) को धारा के साथ संयुक्त रूप से पढ़ने पर उक्त अधिनियम के 53 के संबंध में, इस न्यायालय की राय है कि गैर अनुमोदित शिक्षकों के लिए भी शिकायत समिति है शिकायत पर विचार करने और वैधानिक कार्रवाई करने का अधिकार क्षेत्र उक्त अधिनियम की धारा 53 के तहत इसे अभ्यास प्रदान किया गया।

21. धारा 2 (35) के अंतर्गत शिक्षकों की परिभाषा व्यापक है गैर-अनुमोदित शिक्षक को भी शामिल करने के लिए पर्याप्त है। वास्तव में कहा गया है परिभाषा के दो भाग हैं, पहला भाग पूर्णकालिक से संबंधित है अनुमोदित प्रदर्शनकारी, शिक्षक, सहायक व्याख्याता, व्याख्याता आदि और दूसरा भाग अन्य व्यक्तियों को पढ़ाने या पढ़ाने से संबंधित है संबद्ध महाविद्यालयों या विश्वविद्यालय में अनुमोदित संस्थान में पूर्णकालिक हसिस पर निर्देश दे रहा है।

22. यद्यपि अनुमोदित शिक्षक एवं वे 'अन्य' शिक्षा देने वाले और निर्देश देने वाले व्यक्ति दो भागों में बंट जाते हैं ई अलग-अलग वर्गों की परिभाषा में दोनों को शामिल किया गया है अधिनियम की धारा 2 (35) के तहत शिक्षक। पहले 'और' शब्द 'अन्य व्यक्ति' लोग विभक्तिवाचक है और एक अलग वर्ग का संकेत देता है।

23. एक वर्ग अपने अंदर समाहित करने वाली एक वैचारिक रचना है एफ समान विशेषताओं वाले व्यक्तियों की कई श्रेणियां। यहां 'अन्य व्यक्तियों' के समूह में वे लोग आते हैं, जो पूर्णकालिक होते हैं आधार पर संबद्ध महाविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं या निर्देश दे रहे हैं विश्वविद्यालय के साथ और वे शिक्षक भी हैं तो भी अस्वीकृत ऐसा प्रतीत होता है कि यह अधिनियम धारा 2(35) का अभिप्राय है।

24. इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता कि 5वें और 6वें प्रतिवादी थे प्रतिवादी में पूर्णकालिक आधार पर शिक्षण में लगे हुए हैं कॉलेज, जो अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय का एक संबद्ध कॉलेज है।

25. यह न्यायालय यह मानने के लिए बाध्य है कि माननीय के सिद्धांत की उच्च न्यायालय ने उचित सराहना नहीं की है धारा 2(35) के दायरे को समझने में ईजुस्डेम जेनेरिस अधिनियम की धारा 53 के साथ पढ़ें।

26. लैटिन अभिव्यक्ति "एजुसडेम जेनेरिस" जिसका अर्थ है 8 "एक ही प्रकार या प्रकृति के" निर्माण का एक सिद्धांत है, इसका अर्थ तब होता है जब वैधानिक पाठ में सामान्य शब्द होते हैं प्रतिबंधित शब्दों से घिरे, सामान्य शब्दों के अर्थ के अर्थ के साथ निहितार्थ द्वारा प्रतिबंधित माना जाता है प्रतिबंधित शब्द. यह एक सिद्धांत है जो "से" उत्पन्न होता है भाषाई निहितार्थ जिसके द्वारा शब्दों का शाब्दिक रूप से विस्तृत सी होता है अर्थ (जब अलगाव में लिया जाता है) को कम माना जाता है मौखिक संदर्भ द्वारा दायरा।" इसे एक उदाहरण के रूप में माना जा सकता है दीर्घवृत्त का, या निहितार्थ पर निर्भरता। यह सिद्धांत माना गया है जब तक कोई विपरीत संकेत न हो तब तक आवेदन करें (देखें ग्लेनविले विलियम्स, 'द ओरिजिन्स एंड लॉजिकल इंप्लीकेशंस ऑफ द एजुस्डेम डी जेनेरिस नियम' *7* रूपांतरण (एनएस) 119)।

27. यह एजुस्डेम जेनेरिस सिद्धांत का एक पहलू है नोस्किटुर ए सोसाईज़ का सिद्धांत। लैटिन कहावत नोस्किटुर सोसाइटी का विचार है कि एक वैधानिक शब्द को उसके ई द्वारा मान्यता प्राप्त है सम्बंधित शब्द. लैटिन शब्द 'सोशियस' का अर्थ 'समाज' है। इसलिए, जब सामान्य शब्दों की तुलना विशिष्ट शब्दों से की जाती है शब्द, सामान्य शब्दों को अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता। उनका रंग और उनकी सामग्री उनके संदर्भ से प्राप्त की जानी है [देखें अटॉर्नी जनरल एफ में विस्काउंट सिमंड्स की इसी

तरह की टिप्पणियाँ वी. हनोवर के प्रिंस अर्नेस्ट ऑगस्टस, (1957) एसी 436 एट 461 रिपोर्ट का]

28. लेकिन निर्माण के अन्य सभी भाषाई सिद्धांतों की तरह, एजुस्डेम जेनेरिस सिद्धांत तभी लागू होता है जब इसके विपरीत हो इरादा नज़र नहीं आता. तत्काल मामले में, एक विपरीत इरादा 'शिक्षक' की परिभाषा में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है जैसा कि ऊपर बताया गया है, उक्त अधिनियम की धारा 2(35) के तहत है दो भागों में. पहला भाग प्रगणित श्रेणियों से संबंधित है लेकिन दूसरा भाग जो शुरू होता है। अभिव्यक्ति द्वारा "और अन्य" व्यक्तियों की एक अलग श्रेणी की परिकल्पना करता है। यहाँ 'और' है विच्छेदनात्मक तो, ऐसी परिभाषा की व्याख्या करते समय सिद्धांत एजुस्डेम जेनेरिस को लागू नहीं किया जा सकता।

29. इस सन्दर्भ में हमें यह याद रखना चाहिए क़ाज़ी बनाम क़ाज़ी में लॉर्ड स्कार्मन द्वारा दी गई सावधानी - ((1979) 3 ऑल-इंग्लैंड रिपोर्ट 897]। रिपोर्ट के पृष्ठ 916 पर, विद्वान कानून भगवान ने यह प्रासंगिक अवलोकन किया: -

> "यदि किसी क़ानून का विधायी उद्देश्य ऐसा है जो वैधानिक है श्रृंखला को एजुस्डेम जेनेरिस पढ़ा जाना चाहिए, ऐसा ही होगा; नियम सहायक है, लेकिन, यदि ऐसा नहीं है, तो नियम के विफल होने की अधिक संभावना है। क़ानून के

> उद्देश्य को पूरा करने के बजाय। नियम, कई लोगों की तरह वैधानिक व्याख्या के अन्य नियम, एक उपयोगी सेवक है लेकिन एक बुरा स्वामी।"

30. यह न्यायालय ईजुस्डेम के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए जेनेरिस ने के.के. के मामले में भी इसी तरह के सिद्धांत दिए। कोचुनी बनाम मद्रास और केरा राज्य, [एआईआर 1960 एससी 1080]। इस न्यायालय की संविधान पीठ कोचुनी (सुप्रा) में बोल रही है न्यायमूर्ति सुब्बा राव (जैसा कि उस समय उनका आधिपत्य था) के माध्यम से रिपोर्ट के पृष्ठ 1103 पर ई पैराग्राफ 50 पर विचार किया गया:-

> "...नियम यह है कि जब सामान्य शब्द विशेष के बाद आते हैं और सा!'ले प्रकृति के विशिष्ट शब्द, सामान्य शब्द अवश्य होने चाहिए उन जैसी ही चीजों तक ही सीमित रहें निर्दिष्ट. लेकिन यह स्पष्ट रूप से निर्णयित मामलों द्वारा निर्धारित किया गया है विशिष्ट शब्दों को एक विशिष्ट जीनस या श्रेणी बनाना चाहिए। यह कानून का अनुल्लंघनीय नियम नहीं है, बल्कि केवल अनुमेय है इसके विपरीत किसी संकेत के अभाव में अनुमान।"

(जोर दिया गया)

31. फिर से इस न्यायालय में एक और संविधान पीठ का निर्णय अमर चंद्र चक्रवर्ती बनाम कलेक्टर के मामले में, उत्पाद शुल्क, सरकार. त्रिपुरा का; अगरतला. और अन्य, एआईआर 1972 एससी 1863 में जस्टिस दुआ के माध्यम से बोलते हुए भी यही बात दोहराई गई रिपोर्ट के पृष्ठ 1868 पर पैराग्राफ 9 में सिद्धांत पर एजुस्डेम जेनेरिस का सिद्धांत, सीखा हुआ जज में देखा गया। इस प्रकार है:-

> "...एजुस्डेम जेनेरिस नियम सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है विशिष्ट और सामान्य शब्दों के बीच असंगति। यह सिद्धांत तब लागू होता है जब (i) क़ानून में 8 शामिल हो विशिष्ट शब्दों की गणना; (ii) के विषय गणना एक वर्ग या श्रेणी का गठन करती है; (iii) वह वर्ग या श्रेणी गणना से समाप्त नहीं होती है; (iv) सामान्य पद गणना का अनुसरण करता है; और (v) कोई नहीं है एक अलग विधायी इरादे का संकेत।"
>
> (जोर दिया गया)

32. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, तत्काल मामले में, एक वैधानिक है इसके विपरीत संकेत. इसलिए जहां वैधानिक है धारा ओ के तहत शिक्षक की परिभाषा के विपरीत संकेत 2(35) को एजुस्डेम जेनेरिस के आधार पर नहीं पढ़ा जा सकता और न ही पढ़ा जा सकता है यह

परिभाषा केवल अनुमोदित शिक्षकों तक ही सीमित रहेगी। अगर ऐसा है किया गया, तो धारा के अंतर्गत परिभाषा का एक बड़ा हिस्सा 2(35) निरर्थक हो जाएगा। वह तो इसके ही विरुद्ध है एजुस्डेम जेनेरिस के सिद्धांत का सार। का उद्देश्य यह सिद्धांत विशिष्ट के बीच किसी भी असंगतता को सुलझाने के लिए है और सामान्य शब्द ताकि किसी क़ानून में सभी शब्द दिए जा सकें प्रभाव और कोई भी शब्द अनावश्यक नहीं हो जाता (सदरलैंड देखें: वैधानिक निर्माण, 5 वां संस्करण, पृष्ठ 189, खंड 2 ए)।

33. यह निर्माण के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है कि किसी भी क़ानून की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है कि उसके एक हिस्से को बेकार कर दिया जाए।

34. इसलिए, यह स्पष्ट है कि जहां एक अलग विधायी इरादा है, क्योंकि इस मामले में, परिभाषा के एक हिस्से को पूरी तरह से निरर्थक बनाने के लिए एजुस्डेम जेनेरिस के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है।

35. धारा 2015 के अंतर्गत 'शिक्षकों' की इतनी संकीर्ण एवं संक्षिप्त व्याख्या देकर उच्च न्यायालय ने न केवल धारा 2(35) के एक भाग को नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन दुर्भाग्य से इसमें एक व्याख्या भी दी गई है जो अधिनियम की धारा 53 के स्वीकृत उद्देश्य के साथ असंगत है।

36. शिकायत समिति के गठन का उद्देश्य अधिनियम की धारा 53 के तहत 8 एक प्रभावी शिकायत प्रदान करना है शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के लिए समाधान मंच। कोई अधिनियम की धारा 2 (35) के तहत 'शिक्षकों' की व्याख्या धारा 2 (35) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को पहुंच से वंचित करता है उक्त मंच के प्रमुख उद्देश्य को पूरी तरह से रद्द कर देता है ऐसा फोर्म बना रहा हूं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह अस्वीकृत है शिक्षकों को इस मंच के संरक्षण की सबसे अधिक आवश्यकता है अनुमोदित शिक्षक. ऐसा मंच बनाकर विश्वविद्यालय वस्तुतः लोको-पेरेंटिस के रूप में अपने अधिकार और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया शिक्षकों पर - स्वीकृत और अस्वीकृत दोनों और कौन हैं से सम्बद्ध विभिन्न महाविद्यालयों में कार्यरत हैं। विचार देना है ऐसे शिक्षकों एवं कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की सुरक्षा से सुरक्षा प्रदान की जायेगी उत्पीड़न जो उन्हें अपने कार्यस्थल पर प्राप्त हो सकता है। ऐसे मंच का निर्माण 'गरिमा' की रक्षा के अनुरूप है व्यक्ति की' जो मूल संवैधानिक अवधारणाओं में से एक है।

37. इसलिए, एजुस्डेम जेनेरिस का सिद्धांत नहीं हो सकता इस प्रमुख वैधानिक उद्देश्य को विफल करने के लिए सेवा में लगाया गया। इस संदर्भ में हम उपयोगी ढंग से उनकी टिप्पणियों को याद कर सकते हैं गाइ टी. हेल्वरिंग बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय। स्टॉकहोम

एनस्किल्डा बैंक, 293 यूएस 84, 88-89, 79 एल ईडी 211, 55 एस सीटी 50, 52 (1934), निम्नानुसार:-

> "हालांकि नियम सुस्थापित और उपयोगी है, यह है, वैधानिक निर्माण के अन्य सिद्धांतों की तरह, केवल एक सहायता क़ानून के सही अर्थ का पता लगाना। यह है न तो अंतिम और न ही विशिष्ट। का अर्थ जानने के लिए क़ानून के शब्द, उन्हें सभी के परीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है वैधानिक निर्माण के उपयुक्त सिद्धांत, जिनमें से एजुस्डेम जेनेरिस का नियम केवल एक है। यदि, विचार करने पर सीपीएनटेक्स्ट और प्राप्त की जाने वाली वस्तुओं की और समग्र रूप से अधिनियम में, यह पर्याप्त रूप से प्रतीत होता है कि सामान्य शब्दों का प्रयोग प्रतिबंधित अर्थ में नहीं किया गया नियम द्वारा सुझाए गए, हमें प्रभावी करना चाहिए वसीयत के क्रम में व्यापक दृष्टिकोण द्वारा निष्कर्ष निकाला गया विधानमंडल का नहीं होगा।"
>
> (जोर दिया गया)

38. इसलिए, बड़े सम्मान के साथ, इस न्यायालय का मानना हैं कि माननीय उच्च न्यायालय संभवतः एक त्रुटि में पड़ गया यह मानते हुए कि शिकायत समिति का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है तब से 5 वें और 6 वें

प्रतिवादी द्वारा की गई शिकायतों पर विचार करें वे अनुमोदित शिक्षक नहीं हैं।

39. विभिन्न अन्य तथ्यात्मक पहलुओं पर विचार किया गया हाई कोर्ट लेकिन जब से हाई कोर्ट का फैसला आया है गलत निष्कर्ष कि शिकायत समिति के पास नहीं है 5 वीं और 6 वीं द्वारा दायर शिकायत से निपटने का क्षेत्राधिकार प्रतिवादी, उच्च न्यायालय के फैसले का आधार ही दुर्भाग्य से त्रुटिपूर्ण है और इसे कायम नहीं रखा जा सकता।

40. उपरोक्त कारणों से अपील स्वीकार की जाती है। हाई कोर्ट का फैसला रद्द किया जाता है।

41. उच्च न्यायालय अब रिट याचिका ई का निपटारा करेगा यहां पहले की गई टिप्पणियों के आलोक में इसके समक्ष दायर किया गया शिकायत समिति के अधिकार क्षेत्र के बारे में। तथापि, यह न्यायालय यह स्पष्ट करता है कि बहाली का आदेश दिया गया है 5 वें और 6 वें प्रतिवादी के संबंध में बनाए रखा जाएगा और एफ का पालन किए बिना उनकी सेवा में निरंतरता को भंग नहीं किया जा सकता विश्वविद्यालय अधिनियमों और क़ानूनों का प्रावधान।

42. उल्लिखित निर्देशों के साथ अपील स्वीकार की जाती है यहाँ ऊपर. पार्टियों को अपना खर्च स्वयं वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

के.के.टी. अपील की अनुमति

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल ''सुवास'' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मुकेश कुमार रेगर आरजेएस द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः- यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सिमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।